eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

विकसित भारत के निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका: एक विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. राजबहादुर मौर्य[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, बुंदेलखंड कॉलेज झाँसी, उत्तर प्रदेश

Received: 08 November 2025, Accepted: 20 November 2025, Published online: 30 November 2025

Abstract

भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। बेशक सरकार और सरकारी उद्यम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताक़त और क्षमता लगा देंगे। हम सभी इस बात से वाक़िफ़ हैं कि भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। बावजूद इसके हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी भी बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास को गति देने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है। निरंतर देश में नवाचार को प्रोत्साहित करना और लोगों को उससे जोड़ना होगा। बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना होगा। वैश्विक बाज़ार में अपने निर्यात को बढ़ावा देना होगा। ज़ाहिर तौर पर इस तीव्र विकास और उत्पादन को भारी निवेश की ज़रूरत होगी और यह काम बिना निजी निवेश और भागीदारी के सम्भव नहीं होगा। सार्वजनिक– निजी भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के विकास में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका होगी और रहेगी।

मुख्य शब्द– विकसित भारत, विनिर्माण, निजी क्षेत्र, विकसित राष्ट्र, आर्थिक विकास, वैश्विक बाज़ार

Introduction

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आर्थिक विकास केवल सरकार की योजनाओं या सार्वजनिक उपक्रमों से ही सम्भव नहीं है। वहाँ पर निजी क्षेत्र अर्थात् कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2001-02 में देश में कुल कम्पनियों की संख्या 1,28,549 थी जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या 1,10,634 थी । अर्थात् कुल कम्पनियों का 86.1 प्रतिशत निजी क्षेत्र में था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में मात्र 11.67 फ़ीसदी कम्पनियाँ थीं और संयुक्त क्षेत्र में 2,048 अर्थात् 1.6 प्रतिशत कम्पनियाँ थीं । उपरोक्त तीनों प्रकार के स्वामित्व को छोड़कर अन्य केवल 920 कम्पनियाँ थीं । आज हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर (जिसमें बड़े निजी उद्योग, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP), विनिर्माण उद्योग, सेवा-उद्योग, स्टार्ट-अप्स आदि शामिल हैं) ने कैसे आर्थिक वृद्धि, सामाजिक परिवर्तन तथा समावेशी विकास में भूमिका निभाई है, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और आगे क्या सम्भावनाएँ हैं।

भारत में बहुराष्ट्रीय निगम - भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की उपस्थिति और भूमिका आज़ादी के पहले से ही रही है । स्वतंत्र भारत की सरकार ने शुरुआती दौर में विदेशी पूंजी के प्रति थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई परन्तु शीघ्र ही वह सहनशीलता में बदल गयी । 1948 के पहले औद्योगिक नीति वक्तव्य में केवल भारतवासियों को औद्योगिक कम्पनियों का मालिकाना हक़ देने का आग्रह शामिल था, लेकिन साल भर बाद ही सरकार सीमित अवधि के लिए किसी कम्पनी पर विदेशी नियंत्रण के लिए राज़ी हो गयी । इसी के बाद से 1959 तक **फ़ायरस्टोन, डनलप, बाटा, हिन्दुस्तान लीवर** जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति मज़बूत होती चली गयी । साठ के दशक के मध्य तक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाने की हैसियत प्राप्त कर चुकी थीं ।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

इन कम्पनियों के महत्व में दूसरा निर्णायक उछाल नब्बे के दशक में आया जब ढांचागत समायोजन कार्यक्रम और उदारीकरण की नीतियों के कारण इन कम्पनियों के लिए अर्थव्यवस्था ने अपने दरवाज़े पूरी तरह से खोल दिए । वर्ष 1966 में भारत में कार्यरत सबसे बड़ी 112 कंपनियों में से 62 का स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी हाथों में था । बहुत सी भारतीय कंपनियाँ उनके साथ तकनीकी सहयोग समझौते के ज़रिए जुड़ी हुई थीं । सत्तर के दशक के अंत में देश में विदेशी मुद्रा संकट ने अर्थव्यवस्था को घेर लिया और सरकार को आर्थिक सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास क़र्ज़ लेने के लिए जाना पड़ा । इन्हीं क़र्ज़ की शर्तों में सरकार को अर्थव्यवस्था में समायोजन कार्यक्रम चलाना पड़ा । इसी के तहत माल और प्रौद्योगिकी का आयात सरल बनाया गया । बहुराष्ट्रीय निगमों को अपनी शेयर पूंजी बढ़ाने का अवसर मिला । निर्यात और प्रौद्योगिकी प्रधान क्षेत्रों में उन्हें सौ फ़ीसदी मिल्कियत रखने का अधिकार मिल गया । सरकार ने कारपोरेट आयकर भी घटा दिया जिससे विदेशी निवेश को और अधिक प्रोत्साहन मिला । 1981 से 1985 के बीच सुजुकी, दुपोंत, मित्सबुशी, गुडइयर और सीको जैसे नए बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारत में प्रवेश किया । वेस्टिंगहाउस, जरोक्स, युनाइटेड टेक्नोलॉजी और हनीवेल जैसे निगम भारतीय कम्पनियों से समझौते करके यहाँ के बाज़ार में आ गये ।(1) वर्ष 1991 में सरकार फिर से विदेशी मुद्रा क़र्ज़ लेने के लिए ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की शरण में गयी और विश्व बैंक व मुद्रा कोष ने एक नया ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम चलाने की शर्त लगाई । इसके मुताबिक़ 34 उद्योगों के दरवाज़े 51 फ़ीसदी विदेशी स्वामित्व के लिए खोलने पड़े । एक उच्चाधिकार प्राप्त विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड गठित किया गया । मौजूदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना स्वामित्व 51 फ़ीसदी तक बढ़ाने की अनुमति दी गयी। कुछ क्षेत्रों में सौ फ़ीसदी विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी ।(2)

निजी अथवा मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था की पैरोकारी और सहायक संस्थाएँ

ब्रेटन वुड्स प्रणाली :- पूरी दुनिया में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने में ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अहम योगदान है । द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले अगस्त, 1944 में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने 44 राष्ट्रों के एक सम्मेलन के माध्यम से इस प्रणाली को स्थापित किया था । इस सम्मेलन का औपचारिक नाम था इंटरनेशनल मोनेटरी एंड फ़ाइनेंशियल कांफ्रेंस ऑफ द युनाइटेड ऐंड एसोसिएटिड नेशंस । चूँकि इसका आयोजन न्यू हैमशायर की एक छोटी सी सैरगाह ब्रेटन वुड्स में किया गया था इसलिए इसे संक्षेप में इसी नाम से जाना जाता है । ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत ही विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गयी । कालांतर में इस संस्था ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया जो इस समय विश्व व्यवस्था के शिखर पर है । इस कांफ्रेंस की संकल्पना और कामयाबी में अमेरिका के अर्थमंत्री हैरी व्हाइट और ब्रिटेन के प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रमुख भूमिका थी । ब्रेटन वुड्स प्रणाली के केंद्र में निर्धारित विनिमय दर जिसके तहत विश्व की सभी मुद्राओं का आकलन आईएमएफ़ द्वारा डॉलर के मुताबिक़ किया जाना था और डॉलर का मूल्य स्वर्ण मानक के हिसाब से तय होना था । ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय अमेरिका के पास 25 अरब डॉलर की क़ीमत का सोना जमा था जो दुनिया में पूरे जमा सोने का 75 फ़ीसदी था ।(3)

विश्व बैंक :- वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के तहत स्थापित किए गए विश्व बैंक का पूरा नाम है **इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऐंड डिवलेपमेंट (आई बी आर डी)**। बैंक ने 1946 में जिस समय अपना कामकाज शुरू किया था उस समय कुल 38 देश उसके सदस्य थे और आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग 180 हो चुकी है । विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और संयुक्त राष्ट्र संघ उसे अपनी प्रमुख एजेंसी के रूप में मान्यता देता है । विश्व बैंक सड़क निर्माण, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, बन्दरगाहों के निर्माण और बाँध बनाने जैसी भारी भरकम परियोजनाओं को छोटी और स्थानीय महत्व की परियोजनाओं की

तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है । भारत में विश्व बैंक ने सिंगरोली विद्युत परियोजना और सरदार सरोवर बाँध परियोजना को आर्थिक सहयोग प्रदान किया है ।(4)

विश्व व्यापार संगठन : - विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सात साल तक चलने वाली बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे- चक्र की समाप्ति के साल भर बाद 1 जनवरी, 1995 को गयी । यह वार्ता गैट द्वारा आयोजित की गयी थी । गैट का मकसद केवल कारख़ाना निर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को उदार बनाने तक सीमित था जबकि विश्व व्यापार संगठन का कार्यक्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है । 1999 में इसके सदस्य देशों की सियटल में बैठक हुई जिसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त करने के उद्देश्य से नीतियाँ बनाने के लिए आयोजित किए जाने वाले वार्ता- चक्र की कार्यसूची तय करना था ।विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य देशों के लिए सूचनाओं के आदान- प्रदान, विचार- विमर्श और समझौता वार्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करना है । इसका यह भी उद्देश्य है कि दुनिया में सभी देश व्यापार में भेदभाव वाली नीतियों को न अपनाएँ । इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य देशों के बीच संधियों को बढ़ावा देता है तथा उनके बीच आने वाले विवादों का समाधान भी करता है ।(5)

भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने वाली सरकारी नीतियाँ - भारत सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा अधिक संख्या में औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं । भारत सरकार उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता से तथा उचित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम प्रदान करती है । देश के अंदर किए गए सुधारों के साथ ही सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत उपायों को लागू किया है । इस सिलसिले में सरकार ने एक निवेशक अनुकूल योजना भी प्रारम्भ की है जिसमें कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुले हैं । इसके अलावा भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकल खिड़की पोर्टल विकसित किया है । जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है । यह प्लेटफ़ॉर्म राष्ट्रीय पोर्टल, पैन आधारित सत्यापन और पंजीकरण तथा केन्द्रीय स्तर पर 270 से अधिक जी 2 बी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है । वर्तमान में सरकार ने 32 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और 28 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की एकल खिड़की प्रणालियों की मंज़ूरी को एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया है । कुल 277 केंद्रीय स्वीकृति और 2,977 राज्य मंज़ूरी के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है । राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल के माध्यम से 653 केन्द्रीय स्वीकृति और 6,198 राज्य मंज़ूरी से संबंधित जानकारी व्यवसायों के लिये उपलब्ध है ।(6)

निजी या मुक्त अर्थव्यवस्था के पैरोकार

ऐडम स्मिथ : - बाज़ार के कामकाज को समझने की सर्वाधिक प्रभावशाली कोशिश ऐडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी किताब **वेल्थ ऑफ नेशंस** में की थी । स्मिथ अपने जमाने में सामन्ती गिल्डों और वणिकवादियों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर लगायी जाने वाली पाबन्दियों के विपरीत बाज़ार की मुक्त सक्रियता के पक्ष में थे । उनका कहना था कि बाज़ार एक स्व- विनिमयकारी परिघटना है जिसके तहत् होने वाली स्पर्धा **अदृश्य हाथ** की तरह बिना किसी बाहरी नियंत्रण के आर्थिक जीवन को निर्देशित करती है । स्मिथ की मान्यता थी कि हर व्यक्ति अपने स्व- हित के लिए प्रयासरत रहता है और इस प्रक्रिया में व्यापक सामाजिक हित की उपलब्धि

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

अपने आप हो जाती है, उसके लिए इरादा किया जाए या न किया जाए । स्मिथ के अनुसार स्पर्धा का अदृश्य हाथ ही समृद्धि पैदा करता है । (6A)

विल्फ्रेडो परेटो :- एक इतालवी पिता की संतान विल्फ्रेडो परेटो (1848-1923) ने अपने चिंतन से मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन किया । परेटो ने अपने "अनुकूलतम परिस्थिति के सिद्धांत" का प्रतिपादन करते हुए लिखा कि दो व्यक्ति तभी कोई लेनदेन करते हैं जब दोनों को फायदे की उम्मीद हो । अगर लाभ किसी एक को ही होगा तो विनिमय होगा ही नहीं । ऐसी स्थिति के बावजूद अगर दबाव डालकर वस्तुओं का पुनर्वितरण करने की कोशिश की जाएगी तो कुल मिलाकर स्थिति में या आर्थिक प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होगा । इसलिए बाज़ार में मुक्त विनिमय की स्थिति ही अनुकूलतम कही जा सकती है । परेटो ने मालदार लोगों को टैक्स में छूट देने की भी वकालत की । उन्होंने लिखा, "अगर मालदार लोगों को यह रियायतें मिलेंगी तो वे निवेश ज़्यादा कर सकेंगे और आर्थिक उछाल आएगा और नतीजे के तौर पर ग़रीबों की भी बेहतरी होगी ।" (7)

फ्रेडेरिक वॉन हायक : - वियना में जन्में, मुक्त बाज़ार के लाभों की पैरोकारी करने वाले, ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री फ्रड्रिख वॉन हायक (1899-1992) की मान्यता थी कि सरकार द्वारा किया गया आमदनी का कोई भी पुनर्वितरण अमीरों और ग़रीबों दोनों को नुक़सान पहुँचाने वाला होता है। हायक के अनुसार बाज़ार को नियंत्रित करने का नतीजा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने, आर्थिक दक्षता को घटाने और जीवन स्तर में कटौती करने से निकलता है । आय वितरण का काम बाज़ार की निर्वैयक्तिक ताक़तों पर छोड़ देना चाहिए । बाज़ार के परिणामों को न्याय- अन्याय की कसौटियों पर कसना उचित नहीं होता, क्योंकि न्याय की अवधारणा इस तरह की परिस्थितियों पर लागू नहीं हो सकती । 1944 में हायक की पुस्तक **रोड टु सर्फडम** प्रकाशित हुई जिसने उन्हें सामाजिक सिद्धांतकार के रूप में सारी दुनिया में पहचान दिलाई । 1974 में उन्हें गुन्नार मिर्डाल के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।हायक ने बड़ी निजी फर्मों और बड़े बैंकों को अपनी मुद्रा छापने का अधिकार देने का सुझाव दिया ।(7A)

मिलटन फ्रीडमैन : - बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के चर्चित और विख्यात अर्थशास्त्री मिलटन फ्रीडमैन (1913-2005) को भी अर्थशास्त्र की दुनिया में कीन्सियन आर्थिक सिद्धांतों के खिलाफ और मौद्रिकवाद के संस्थापकों के रूप में जाना जाता है । फ्रीडमैन के रचना संसार के केंद्र में दो विचार हैं : धन और आज़ादी । धन उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा की सप्लाई में होने वाले परिवर्तनों से आर्थिक गतिविधियों में तब्दीली आ जाती है और आज़ादी की अहमियत इसलिए है कि इंसान होने की शर्त उसके बिना पूरी नहीं हो सकती । धन और आज़ादी का रिश्ता फ्रीडमैन की नज़रों में साफ़ है : अगर सरकार क़ीमतों, विनिमय दरों और आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करना बंद कर दे तो अर्थव्यवस्था ठीक से चलती रहेगी और बाज़ार अपने आप ख़ुशहाली की गारंटी कर सकता है । 1976 में मिलटन फ्रीडमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया ।(8)

रॉबर्ट नॉजिक : - अमेरिकी दार्शनिक और स्वतंत्रतावादी विचारक रॉबर्ट नॉजिक (1938-2002) ने वर्ष 1974 में प्रकाशित अपनी विख्यात पुस्तक **एनार्की, स्टेट ऐंड यूटोपिया** में मुक्त अर्थव्यवस्था के पक्ष में खुलकर अपना समर्थन व्यक्त किया है । नॉजिक ने लिखा है कि अगर सम्पत्ति न्यायपूर्ण तौर- तरीक़ों से हासिल या हस्तांतरित की गई हो तो उसके स्वामित्व में किसी क़िस्म का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । न सामाजिक न्याय के नाम पर और न ही समाज के किसी अन्य वृहत्तर हित के नाम पर । लोक कल्याण के नाम पर अपनाई जाने वाली वितरणमूलक नीतियों द्वारा किए जाने वाले सम्पत्ति या संसाधनों के हस्तांतरण को नॉजिक वैध सम्पत्ति

की चोरी करार देते हैं। नॉजिक की मान्यता है कि लोगों को चीजों का स्वामित्व एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के ज़रिए मिलता है, इसलिए उस स्वामित्व को रखने या किसी और को देने का फ़ैसला वे ही अपने विवेकानुसार कर सकते हैं।(9)

निजी क्षेत्र (कॉर्पोरेट सेक्टर) का अर्थ एवं परिप्रेक्ष्य- "कॉर्पोरेट सेक्टर" से तात्पर्य उन व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों और उद्योगों से है, जो लाभ-उन्मुख हैं, स्व-संचालित हैं या सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र से भिन्न हैं। भारत में 1991 की आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत बढ़ी। कॉर्पोरेट सेक्टर का विकास निम्नलिखित बिंदुओं से जुड़ा हुआ है: निवेश और पूँजी जुटाना, श्रम-शक्ति को रोजगार देना, नवाचार और प्रतियोगिता बढ़ाना, वैश्विक बाजारों में भागीदारी, सामाजिक एवं पर्यावरण-उत्तरदायित्व निभाना।इसलिए, जब हम कहते हैं "कॉर्पोरेट सेक्टर भारत के विकास में भूमिका निभा रहा है", तो यह सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है बल्कि रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण-सुरक्षा आदि का समुचित संयोजन है।(10)

1-आर्थिक विकास में योगदान

निवेश और पूँजी निर्माण- कॉर्पोरेट कंपनियाँ बड़े पैमाने पर निवेश करती हैं — औद्योगिक इकाइयाँ, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, निर्यात-उद्योग आदि। उदाहरणस्वरूप, यह पाया गया है कि भारत में निजी क्षेत्र (पीवीटी सेक्टर) "निवेश, रोजगार, नवाचार" के प्रमुख स्रोत हैं। सरकारी नियामक दस्तावेज़ बताते हैं कि कॉर्पोरेट स्वरूप (company form) भारत में तेजी से उभरा है — "1956 में करीब 30,000 कंपनियाँ थीं, आज लगभग 9 लाख" (संयुक्त परिसंख्या) के रूप में।(11)

रोजगार सृजन- जब कंपनियाँ विस्तार करती हैं, उत्पादन बढ़ाती हैं या सेवा-क्षेत्र में प्रसार करती हैं, तो लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने से आय बढ़ती है, जीवन-स्तर सुधरता है, उपभोग क्षमता बढ़ती है और अन्ततः अर्थव्यवस्था में चक्र चलता है। वर्ष 2001-02 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में 44.3 फ़ीसदी रोज़गार था जबकि इसी दौर में निजी क्षेत्र में 51.2 प्रतिशत रोज़गार उपलब्ध था। इस दौरान संयुक्त उद्यमों में 4 फ़ीसदी रोज़गार था जबकि अन्य क्षेत्रों में मात्र 0.6 फ़ीसदी रोज़गार उपलब्ध था। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इसी दौरान कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र का योगदान 66 फ़ीसदी था जबकि सरकारी क्षेत्र का योगदान केवल 22 प्रतिशत था। (www.economics discussion.net) इसके अलावा भारत में SMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) की संख्या करीब 4,800 लाख है, और इनका श्रम-शक्ति पर बड़ा प्रभाव है।(12)

विनिर्माण एवं निर्यात बढ़ावा- कॉर्पोरेट सेक्टर ने विनिर्माण ('मैन्युफैक्चरिंग') पर विशेष ध्यान दिया है। सूचना-प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुएँ, दिग्गज उद्योग इत्यादि में कंपनियों ने निवेश किया है। यह निर्यात-क्षमता को बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, तथा भारत वैश्विक आपूर्ति-शृंखला (supply chain) में शामिल होता है। ICSI+1 वर्ष 2004 में भारत में रिलायंस ने 70,196 करोड़ रुपये की नेट बिक्री की। जबकि टाटा मोटर्स ने 13,654 करोड़, टाटा स्टील ने 11,129 करोड़, लारसन एंड टर्बो ने 10,849 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 10,837 करोड़, मारुति उद्योग ने 9,426 करोड़, अड़ानी एक्सपोर्ट ने 8,921 करोड़, हिंडालको ने 8,196 करोड़, आई पी सी एल ने 8,070 करोड़ तथा स्टर्लिंग इंडिया ने 7,699 करोड़ रुपए की नेट सेल किया। इस प्रकार कुल मिलाकर 80 प्रतिशत कार्यबल निजी क्षेत्र के पास है। (13)

नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा- कॉर्पोरेट कंपनियाँ अनुसंधान-विकास (R&D) में सक्रिय रही हैं, नए उत्पाद, नए व्यापार मॉडल ला रही हैं। उदाहरण के लिए, निजी क्षेत्र 'स्टार्ट-अप्स' को समर्थन देता है, नए उद्यमों को बढ़ाने का काम करता है। यह सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि उत्पादकता (productivity) और प्रतिस्पर्धात्मकता (competitiveness) को भी बढ़ावा देना है।(14)

2-सामाजिक व मानवीय विकास में भूमिका

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)- भारत में 2013 के बाद से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कानूनी रूप से महत्व-पूर्ण हो गया है। (15) CSR के माध्यम से कंपनियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। उदाहरण स्वरूप: आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समावेशन का पहलू जोड़ना। (16) ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने की कोशिश। (17)

कौशल विकास एवं रोजगार-उन्मुख पहल- कॉर्पोरेट सेक्टर ने कौशल (skilling) एवं प्रशिक्षण (training) कार्यक्रमों को अपनाया है — ताकि श्रम-शक्ति बेहतर बने, अधिक उत्पादक हों। उदाहरणस्वरूप, National Skill Development Corporation (NSDC) जैसी गतिविधियों में निजी-साझेदारी मॉडल सामने आया है। (18) यह मॉडल युवाओं को रोजगार योग्य बनाता है, उन्हें उद्योग-ज़रूरतों के अनुरूप तैयार करता है।

सामाजिक समावेशन और ग्रामीण-विकास- कॉर्पोरेट्स ग्रामीण इलाकों में निवेश, आधारभूत सुविधा-उन्नयन, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य-शिक्षा केंद्र स्थापित करने में भाग ले रहे हैं। इस तरह, विकास केवल शहरी केंद्रित नहीं रह जाता, बल्कि दूरदराज के इलाकों में भी असर देखने को मिलता है।

पर्यावरण एवं सतत विकास - आज कॉर्पोरेट्स को सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि पर्यावरण-सुरक्षा (environmental sustainability) और सामाजिक-उत्तरदायित्व (social responsibility) को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भारत ने "National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business" नामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो इस दिशा में मार्गदर्शक हैं। (19) उदाहरणस्वरूप, कंपनियाँ ऊर्जा-क्षमताओं को सुधार रही हैं, अपशिष्ट प्रबंधन कर रही हैं, संसाधन-प्रबंधन पर ध्यान दे रही हैं।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) और भूमिका- कॉर्पोरेट सेक्टर सिर्फ खुद के निवेश से ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल में भाग लेता है। इससे बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि में सुधार होता है। (20) उदाहरण के लिए – एक कंपनी किसी सरकारी स्कूल का दत्तक लेती है (adopt) और उसे बेहतर बनाती है; या स्वास्थ्य-केंद्र को निजी सहयोग से चलाती है। इस तरह, सामाजिक विकास और व्यावसायिक संसाधन का संयोजन संभव होता है।

3- चुनौतियाँ एवं सीमाएँ- हालाँकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत योगदान दिया है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ एवं सीमाएँ भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

असममित विकास- कॉर्पोरेट निवेश अक्सर शहरी क्षेत्रों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या बड़े केंद्रों में केंद्रित रहता है। इससे ग्रामीण-और पिछड़े इलाकों में विकास की गति कम हो सकती है।

विनियामक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ- कंपनियों को नियम-कानून, पारदर्शिता, व्यावसायिक-शासन (corporate governance) आदि में संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, निगम-कानून, श्रम-कानून, पर्यावरण-कानून आदि। (21)

कौशल व मानव संसाधन की कमी- बहुत सी कंपनियों को कौशल-सम्पन्न श्रमिकों की कमी, प्रशिक्षण-व्यवस्था की कमी, अनियमित श्रम-बाजार की समस्या रहती है। (22)

सामाजिक उत्तरदायित्व की वास्तविकता- जब CSR की बात आती है, तो कभी-कभी यह आर्थिक लाभ का एक भाग मात्र बन जाता है, न कि समाज-हित का सृजन-तत्व। इसलिए इसकी गुणवत्ता, निरंतरता, प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। (23)

भारत की विकास-यात्रा में कॉर्पोरेट सेक्टर का सामंजस्य- भारत ने 1991 के बाद से आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की दिशा में कदम उठाए हैं। इस यात्रा में कॉर्पोरेट सेक्टर ने निम्न-प्रकार से योगदान किया है : अर्थव्यवस्था को तेज गति देना (जीडीपी वृद्धि में योगदान), नए उद्योग-क्षेत्रों का विकास (आईटी, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण), वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बदलाव, नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना, सामाजिक-विकास कार्यक्रमों में समावेश तथा देश के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना और भारत को वैश्विक निवेश गंतव्य बनाना। (24) इसके अलावा, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुरमू ने जून 2025 में कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर देश की आर्थिक वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। (25)

"विकसित भारत@2047" के दृष्टिकोण से भूमिका- भारत ने "विकसित भारत" बनाने का लक्ष्य रखा है—जिसमें समृद्धि, समता, सततता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता शामिल हैं। इस लक्ष्य तक पहुँचने में कॉर्पोरेट सेक्टर की भूमिका निम्न प्रकार से महत्त्वपूर्ण होगी: विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, ताकि रोजगार उत्पन्न हो और व्यापार संतुलन बेहतर हो। डिजिटल तकनीक, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा-कुशल उत्पादन में आगे आना। कौशल विकास द्वारा युवाओं को तैयार करना और "डेमोग्राफिक डिब्बेंडेंट" को अवसरों में बदलना। सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को अपने व्यापार मॉडल में समाहित करना (ESG – पर्यावरण-सामाजिक-शासन) । ग्रामीण-शहरी असंतुलन को दूर करने के लिए निजी निवेश को पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँचाना। नव-उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना, जिससे नई अर्थव्यवस्थाएँ विकसित हों। यदि कॉर्पोरेट सेक्टर इन दिशाओं में सक्रिय रहेगा, तो "भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थान दिलाना" संभव हो सकेगा।

बहुराष्ट्रीय निगमों का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव - बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने उत्पाद से हमारे दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है । सुबह की पहली चाय और प्याले से लेकर दाँत साफ़ करने के लिए बने पेस्ट और टूथब्रुश लाज़मी तौर पर किसी न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पाद होते हैं । पूरी सम्भावना रहती है कि हमारे टीवी, सेलफोन, म्यूज़िक सिस्टम, कम्प्यूटर, घर में काम आने वाले साधारण से उपकरण, पहनने और बिछाने वाले कपड़े, पैरों के जूते, पेय पदार्थ, धूम्रपान के लिए सिगरेट, आवागमन के लिए कार, लिखने के लिए कलम और भी न जाने क्या-क्या अर्थात् तक़रीबन सभी चीज़ें किसी न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की ही देन हों । अब इस सूची में बैंकों, बीमा कंपनियों और अस्पतालों का भी नाम जुड़ गया है । कुल मिलाकर जीवन के हर क्षेत्र में यह कम्पनियाँ प्रभावी हो चुकी हैं । यह हमारे आचार- व्यवहार, सोच- विचार, खानपान और सांस्कृतिक अभिरुचियों को भी प्रभावित करती हैं । आज ग्लोबल अर्थव्यवस्था की लगाम इन्हीं बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में है । सारी दुनिया में क़रीब 53,000 बहुराष्ट्रीय निगम हैं जिनकी 4,50,000 सहायक कंपनियाँ हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि कई विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अस्पतालों, स्कूलों और

उपयोगी अधिरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना में योगदान दिया है । इसके कारण रोज़गार, प्रशिक्षण और शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हुई है । (26)

निष्कर्ष- संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो – भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर विकास-यात्रा का अभिन्न अंग रहा है। केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन, रोजगार-उन्मुखता, नवाचार, कौशल विकास तथा सततता में भी उस का योगदान दिख रहा है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं कि विकास को समावेशी, संतुलित और पर्यावरण-मित्र बनाना। इसके साथ ही निजी क्षेत्र बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था है, जहाँ समानता एक मूलभूत स्थिति है क्योंकि वह व्यक्ति का मूल्यांकन योग्यता, प्रतिभा और कठोर परिश्रम की क्षमता के हिसाब से करता है, न कि नस्ल, चमड़ी के रंग, धर्म, जेंडर आदि के आधार पर । विभिन्न लेयरों (उद्योग, सेवा, स्टार्ट-अप, ग्रामीण निवेश, CSR आदि) में कॉर्पोरेट सेक्टर की सक्रिय भागीदारी से न सिर्फ आज बल्कि आने वाले दशकों में "विकसित भारत" का सपना साकार होता दिख रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस भागीदारी का लाभ सभी तक पहुँचे — शहर-गाँव, अमीर-गरीब, पुरुष-महिला — तथा विकास आर्थिक मॉडल से आगे निकलकर सामाजिक-मानवीय मॉडल बने।

सुझाव

- कंपनियों को सिर्फ लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक-उत्तरदायित्व और पर्यावरण-प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए । सरकार-निजी सेक्टर सहयोग (PPP) को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, विशेषकर पिछड़ों में। कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण एवं रोजगार-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। उचित कॉर्पोरेट-शासन (corporate governance), पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। ग्रामीण-शहरी एवं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए निजी निवेश को प्रेरित करना चाहिए। नव-उद्यमियों (start-ups), SMEs तथा नवाचार-पर आधारित मॉडल को समर्थन देना चाहिए।

संदर्भ / स्रोत

1- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -4, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर 1143,1144

2- उपरोक्त, पेज नंबर 1144

3- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -3, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नम्बर -1059,1060

4- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -5, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नम्बर- 1773

5- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -5, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर- 1771,1772

6- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, pib.gov.in/Press Releas, 06 August 2024

6A- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -3, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर- 1022

7- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -5, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर- 1755,1756

7A- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -3, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर- 978,979

8- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -4, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर- 1450

9- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -3, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर- 800, 801

10-World Economic Forum+2Ministry of Corporate Affairs+2

11-World Economic Forum+1,Ministry of Corporate Affairs

12- PwC

13- www.economics discussion.net

14- PwC+1

15- seer-ufu-br.online+1-

16- World Bank+1

17- ICSI+1

18- Wikipedia+1

19- Wikipedia

20- ICSI

21- Ministry of Corporate Affairs

22- PwC

23- seer-ufu-br.online+1

24- World Economic Forum

25- mint

26- दुबे अभय कुमार, समाज -विज्ञान विश्वकोश , खण्ड -3, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नंबर- 1011, 12, 13

Other article on corporate sector & human development.

A- smsjournals.com+1

B- “What the private sector can do for India’s economic growth” – World Economic Forum. World Economic Forum

C- “Role of Corporate Social Responsibility in Social and Economic Development in India” – Sarojanamma & Ganesh. seer-ufu-br.online

D- “India: Corporate Social Responsibility” – World Bank feature. World Bank

E- “The role of the private sector” – PwC Future of India corporations. PwC

F- Strategic Plan, Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India. Ministry of Corporate Affairs

G- “Role and Significance of Start-Ups for Viksit Bharat@2047” – ICSI Journal. ICSI

H- President Murmu’s speech on corporate sector role. mint+1